



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2009/अग्रहायण 6, 1931

No. 234]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2009/AGRAHAYANA 6, 1931

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 24 नवम्बर, 2009

सं. टीएएमपी/43/2005-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा विशाखापट्टनम पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/43/2005-वीपीटी

आदेश

(अक्तूबर, 2009 के 23वें दिन पारित)

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के वर्तमान प्रचलित दरमान को इस प्राधिकरण ने दिनांक 11 मई, 2006 को पिछली बार दिनांक 11 मई, 2006 के आदेश संख्या टीएएमपी/43/2005-वीपीटी के द्वारा अनुमोदित किया था। आदेश के साथ दरमान को भी भारत का राजपत्र में 5 जून, 2006 को राजपत्र संख्या 96 के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अनुमोदित दरमान की वैधता 31 मार्च, 2009 तक निर्धारित की गई।

2. इस प्राधिकरण ने दिनांक 17 जून, 2009 के आदेश के द्वारा वीपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 30 सितम्बर, 2009 तक विस्तारित किया था। यह आदेश 20 जून, 2009 को भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 108 के द्वारा अधिसूचित किया गया था।

3. वीपीटी ने दरमान के संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल कर दिया है जो संबंधित उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ताओं के संगठनों के साथ विचार-विमर्श के लिए रखा गया है। प्रस्ताव को आंतरिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2009 के द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 तक प्रचलित दरमान की वैधता को विस्तारित करने के लिए अनुरोध किया है या दाखिल प्रस्ताव के अंतिम रूप से निपटाने तक, इसमें से जो भी पहले हो।

5. चूंकि प्रचलित दरमान की वैधता 30 सितम्बर, 2009 को समाप्त होती है, यह प्राधिकरण प्रचलित दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2010 तक या दरमान के संशोधन हेतु वीपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव को अंतिम रूप से निपटाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6. यदि 1 अप्रैल, 2009 के बाद वाली अवधि में लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/09-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th November, 2009

No. TAMP/43/2005-VPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the Scale of Rates at the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/43/2005-VPT

ORDER

(Passed on this 23rd day of October, 2009)

The existing Scale of Rates (SOR) of the Visakhapatnam Port Trust (VPT) was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/43/2005-VPT, dated 11th May, 2006. The Order along with the SOR was published in the Gazette of India on 5th June, 2006 *vide* Gazette No. 96. The validity of the approved SOR was prescribed till 31st March, 2009.

2. The validity of the existing Scale of Rates of the VPT was extended by the Authority till 30th September, 2009 *vide* its Order dated 17th June, 2009. The Order was notified in the Gazette on 20th June, 2009 *vide* Gazette No. 108.

3. The VPT has filed the proposal for revision of its Scale of Rates which is taken on consultation with the concerned port users/user organisations. The proposal is also being scrutinized internally.

4. The VPT *vide* its letter dated 12th September, 2009 has requested to extend the validity of the existing Scale of Rates till 31st December, 2009 or till final disposal of its proposal, whichever is earlier.

5. Since the validity of the existing SOR has expired on 30th September, 2009 and recognizing the time required for finalizing the case, this Authority extends the validity of the existing SOR till 31st March, 2010 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. Additional surplus, if any, over and above the admissible cost and permissible return for the period post 1st April, 2009 will be adjusted fully in the tariff to be determined.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT III/4/143/09-Exty.]